IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 2, November 2025
Impact Factor: 7.67

"राजनीतिक चिंतन : डॉ. राममनोहर लोहिया"

शोध निर्देशक
डॉ. एस.पी शुक्ला
प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग
शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय,
रीवा (म.प्र.)

शोधार्थी
अशोक कोरी
एम.ए., राजनीति विज्ञान
शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय,
रीवा (म.प्र.)

शोध सारांश

राजनीतिक विचारधारा को डॉ. राममनोहर लोहिया के क्षेत्र में सभी सभ्यताओं में अपना प्रारम्भिक समय से ही विचार विमर्श किया है और राज्य में संबंधी मौलिक प्रश्नों को विचार विमर्श किया हैं सभी क्षेत्रों में रहने वाले राजनीतिक विचारधारा के लिए संसार बसा है। डॉ. लोहिया ने इतिहास को कठोरतापूर्वक बनाया जिसके बिना किसी भी भावना के चक्राकार ढंग से रहा। मार्क्स हेगेल और डॉ. लोहिया के द्वारा इतिहास के विकास की व्याख्या को समझकर उनको स्वीकार किया जिससे मार्क्स ने विभिन्न जातियों का उत्थान–पतन के कारण इतिहास के विभिन्न कालों में जातियों की समीचीन के कारण समझाये।

कुछ विचारक है जो पश्चिम में इस सिद्धांत को भी स्वीकार करते हैं। इन विचारकों के विचार से डॉ. लोहिया भी सहमत रहे। वह पतनशील हो सकता है जो देश उन्नति के चरम शिखर पर समय चक्र के दौरान है। वह इन परिस्थिति में है जो पतन अपनी उन्नति शिखर तक उन्नति कर ले और पहुँच जाए। इन राष्ट्रों का उत्थान–पतन डॉ. लोहिया के तहत सभ्यताओं का सदैव होता रहता है। प्रस्तुत शोध पत्र में उपरोक्त बिन्दुओं को समाहित करने का प्रयास है।

मुख्य शब्दः–राजनीतिक, विचारधारा, चिंतन, लोहिया, उन्नति, पतनशील, शिखर, क्षेत्र, साम्राज्य आदि।

प्रस्तावना

इतिहास में कई देशों की तरह चक्राकार गति से घूमता रहा और अभी विकास की सीमा पर है जो इस पतन को अधोगति के पास पहुँचा देता हैं और यदि हम मानव इतिहास का अध्ययन करे तो उन सभी कार्य से यह उन्नत और जातियों का संगठन और सामूहिक वर्गों में संघर्ष के बीच होता है। जिससे वह जातियों के बीच इतिहास के आन्तरिक आंदोलन की शोर गुल का मुख्य कारण अनिवार्य रहा हैं जिससे इतिहास के तरह गतिशीलता प्राप्त करने की आंतरिक हलचल को जाति और वर्ग के बीच रहता है। सभी जातियों को पुरानी परम्पराओं तथा प्रतिक्रियावादी प्रतिनिधित्व शक्ति प्राप्त होती है। इस तरह से सामाजिक गति का विपरीत वर्ग इसके बोध के कारण होता है। जिससे सुनिश्चित रहता है कि जब जातियों के रूप में इन वर्गों की रचना आंतरिक शिथिल होती है। डॉ. राममनोहर लोहिया जी की यह सोच थी कि समाज में कई तरह की बुराइयाँ मनुष्य को जाति एवं वर्गों तक इन सभ्यताओं एवं विचारों के बीच प्रेरक प्रवृत्तियों का संघर्ष होता रहता है और आशावादी, समाज में जाति एवं वर्ग दोनों की भाँति को यह विश्वास रहता है कि इन मानव तक एकता को स्थापित करने में सफल विश्व रहता है।

डॉ. राममनोहर लोहिया जी ने सामाजिक सांस्कृतिक एवं व्यवस्था के वर्तमान आलोचक रहे हैं। जिससे शोषण पर वर्तमान ढाँचा को अन्याय तक रहा है। डॉ. लोहिया जी ने उन सभी क्षेत्रों क्रांतियों का समर्थक को परिवर्तन किया गया है। जिससे डॉ. लोहिया जी का कहना है शक्ति को सामर्थ्य से समतावादी समाज को स्वरूप पूँजी, मानवीय मूल्य रूप से विकसित नहीं रहा है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 2, November 2025 Impact Factor: 7.67

डॉ. राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद (वर्तमान अयोध्या) जिले में अकबरपुर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता हीरालाल लोहिया एक राष्ट्रवादी विचारधारा वाले शिक्षक थे, जिन्होंने लोहिया के बचपन से ही उनमें देशभक्ति और सामाजिक न्याय की भावना विकसित की। लोहिया की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई, जहाँ उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों से गहरी प्रेरणा ली। इसके बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक किया और फिर उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी की प्रसिद्ध बर्लिन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट प्राप्त की। उनकी थीसिस "राष्ट्रीय विचारों का अर्थशास्त्र" पर आधारित थी, जो उनके राष्ट्रवादी और समाजवादी दृष्टिकोण को दर्शाती है।

स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

डॉ. राम मनोहर लोहिया ने अपने छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, तो उन्होंने अन्य राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर उसका विरोध किया, क्योंकि इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसी दौरान वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह से भी प्रभावित हुए।

1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा को संगठित करने के लिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया, तो लोहिया इससे जुड़ गए। वे मार्क्सवाद और गांधीवाद के समन्वय पर विश्वास रखते थे और समाजवादी आर्थिक नीतियों को अपनाने की वकालत करते थे। हालाँकि, उन्होंने नेहरू के समाजवादी दृष्टिकोण की सीमाओं की आलोचना की, क्योंकि वे इसे व्यावहारिक और जनता की समस्याओं के अनुरूप नहीं मानते थे।

1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में लोहिया ने भूमिगत क्रांतिकारी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुप्त रेडियो प्रसारण और आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा मिली। उनकी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा गया। जेल में भी उन्होंने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर देश की भावी सामाजिक और राजनीतिक संरचना पर विचार–विमर्श किया।

जेल से छूटने के बाद भी वे स्वतंत्रता की लड़ाई में सक्रिय रहे और भारत के आजाद होने तक संघर्ष करते रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, उन्होंने अपनी समाजवादी विचारधारा को मूर्त रूप देने के लिए एक नई राजनीतिक दिशा की खोज शुरू की, जिससे वे भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली समाजवादी नेता के रूप में स्थापित हुए।

स्वतंत्र भारत में राजनीति

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात डॉ. राम मनोहर लोहिया भारतीय राजनीति में एक मजबूत विपक्षी स्वर के रूप में उभरे। वे कांग्रेस की नीतियों और शासन प्रणाली के घोर विरोधी थे, क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस की नीतियाँ समाजवादी आदर्शों से भटक रही हैं और केवल एक वर्ग विशेष को लाभ पहुँचा रही हैं। इस विचारधारा को संगठित करने के उद्देश्य से उन्होंने 1952 में अन्य समाजवादी नेताओं के साथ मिलकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया।

हालाँकि, कुछ वर्षों के भीतर ही पार्टी के भीतर वैचारिक मतभेद उभरने लगे। लोहिया एक क्रांतिकारी समाजवाद के पक्षधर थे और वे चाहते थे कि पार्टी जमीनी स्तर पर आम जनता, खासकर किसानों, मजदूरों और पिछड़े वर्गों की समस्याओं को हल करने के लिए आक्रामक रूप से कार्य करे। लेकिन पार्टी के अन्य नेताओं की प्राथमिकताएँ अलग थीं, जिससे मतभेद बढ़ते गए।

इन मतभेदों के चलते 1955 में लोहिया ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। इस नई पार्टी के माध्यम से उन्होंने जातिवाद, आर्थिक असमानता और कांग्रेस के प्रभुत्व के खिलाफ मजबूत आंदोलन छेड़ा। वे सत्ता के विकेंद्रीकरण, सामाजिक न्याय और

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 2, November 2025 Impact Factor: 7.67

वास्तविक लोकतंत्र को लागू करने के प्रबल समर्थक बने रहे। उनके नेतृत्व में समाजवादी विचारधारा भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली आंदोलन के रूप में उभरी, जिसने आगे चलकर कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों को प्रभावित किया।

उद्देश्य :– प्रस्तुत शोध के निम्नानुसार उद्देश्य :–

1. राजनीतिक और सामाजिक चिंतन का अध्ययन करना।
2. डॉ. राममनोहर लोहिया जी के समाजवादी आंदोलनों का अध्ययन करना।
3. डॉ. राममनोहर लोहिया जी के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि :–

प्रस्तुत शोध पत्र में डॉ. राम मनोहर लोहिया जी के विचारों का वर्णात्मक व विवरणात्मक रूप से व्याख्या की गई है। उनके मुख्य विचारों एवं चिंतनपरक सिद्धान्तों तथा राजनीतिकऔर सामाजिक आंदोलनों का लेख किया गया है।

प्रस्तुत शोध आलेख में डॉ. राम मनोहर लोहिया के प्रमुख सिद्धान्तों को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है –

1. समाजवाद और आर्थिक समानता

डॉ. राम मनोहर लोहिया का समाजवाद पारंपरिक मार्क्सवादी विचारधारा से भिन्न था। वे मानते थे कि समाजवाद का लक्ष्य केवल पूँजीवाद का विरोध करना नहीं, बल्कि एक ऐसी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है, जो हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करे और शोषण मुक्त समाज का निर्माण करे। वे निजी संपत्ति के पूर्ण उन्मूलन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन आर्थिक असमानता को समाप्त करने के लिए उन्होंने ठोस नीतियों की वकालत की।

लोहिया ने समाजवाद को केवल आर्थिक बदलाव तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे सामाजिक और राजनीतिक सुधारों से भी जोड़ा। उन्होंने 'सप्त क्रांति' का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें सात प्रमुख क्षेत्रों में परिवर्तन की आवश्यकता बताई गई–

- **आर्थिक समानता**–धन के असमान वितरण को खत्म कर समाज के प्रत्येक वर्ग को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना।
- **जाति प्रथा का अंत**–जातिवादी भेदभाव को समाप्त कर एक समतावादी समाज की स्थापना करना।
- **स्त्री–पुरुष समानता**–महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और अवसर दिलाना।
- **रंगभेद का विरोध**–नस्लीय भेदभाव को खत्म कर सभी मानवों को समान दर्जा देना।
- **उपनिवेशवाद का अंत**–साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी ताकतों का विरोध कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना।
- **व्यक्तिगत स्वतंत्रता**–व्यक्ति की सोच, अभिव्यक्ति और जीवनशैली पर किसी भी प्रकार के अनावश्यक प्रतिबंधों का विरोध करना।
- **अहिंसा**–सामाजिक परिवर्तन के लिए अहिंसक साधनों को प्राथमिकता देना, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अन्य उपायों पर भी विचार करना।

लोहिया का समाजवाद व्यावहारिक था, जो भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। उनका मानना था कि जब तक समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को समान अवसर नहीं मिलते, तब तक समाजवाद का सही उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। उनके विचार आज भी सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता की दिशा में प्रेरणा देते हैं।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 2, November 2025
Impact Factor: 7.67

2. जाति व्यवस्था और सामाजिक न्याय –

डॉ. राम मनोहर लोहिया भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव और ऊँच–नीच की भावना के घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि जब तक समाज में जाति आधारित भेदभाव बना रहेगा, तब तक न तो सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो सकता है और न ही समाजवाद का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इसी विचारधारा के तहत उन्होंने 'जाति तोड़ो आंदोलन' चलाया, जिसका उद्देश्य समाज में व्याप्त ऊँच–नीच की भावना को समाप्त कर सभी को समान अधिकार दिलाना था।

लोहिया मानते थे कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है; इसके साथ–साथ सामाजिक और आर्थिक समानता भी आवश्यक है। उन्होंने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए 'पिछड़ों को 60 प्रतिशत' का नारा दिया। इसका अर्थ था कि सरकार की नौकरियों, शिक्षा संस्थानों और अन्य अवसरों में पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में कम से कम 60 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उनका तर्क था कि भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर रखे गए वर्गों को समान अवसर दिए बिना देश में सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता।

लोहिया ने जाति आधारित विशेषाधिकारों और सामाजिक असमानता को खत्म करने के लिए ठोस नीतियों की वकालत की। वे केवल आरक्षण तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक संरचना में आमूलचूल परिवर्तन लाने के पक्षधर थे। उन्होंने जातिगत भेदभाव को एक गहरी सामाजिक समस्या मानते हुए इसके विरुद्ध जनजागरण किया और लोगों को जातिवाद से ऊपर उठकर एक समतावादी समाज बनाने के लिए प्रेरित किया। उनके ये विचार आज भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनों और नीतियों को दिशा प्रदान करते हैं।

3. गांधी और लोहिया का विचार–साम्य –

डॉ. राम मनोहर लोहिया महात्मा गांधी के विचारों से गहराई से प्रभावित थे, लेकिन उनकी विचारधारा पूरी तरह गांधीवाद से मेल नहीं खाती थी। वे गांधीजी के सत्य, अहिंसा, और स्वराज के सिद्धांतों का समर्थन करते थे, लेकिन वे पूर्ण अहिंसा को हर परिस्थिति में व्यावहारिक नहीं मानते थे। उनका मानना था कि अहिंसा एक नैतिक और राजनीतिक उपकरण के रूप में अत्यंत प्रभावी है, लेकिन जब अन्याय और दमन चरम पर पहुँच जाए, तो क्रांतिकारी कदम उठाना भी आवश्यक हो जाता है।

लोहिया भारतीय समाज और राजनीति में विकेंद्रीकरण के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने गांधीजी की ग्राम स्वराज की अवधारणा को अपनाया और इसे आधुनिक संदर्भ में विकसित करने का प्रयास किया। वे मानते थे कि सत्ता और संसाधनों का केंद्रीकरण न केवल लोकतंत्र को कमजोर करता है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक असमानता को भी बढ़ावा देता है। इसलिए उन्होंने ऐसी नीतियों की वकालत की जो स्थानीय स्वशासन, लघु उद्योगों और ग्रामीण विकास को बढ़ावा दें।

उनका विचार था कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी संभव है, जब लोगों को स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए। वे केवल राजनीतिक विकेंद्रीकरण तक सीमित नहीं थे, बल्कि आर्थिक विकेंद्रीकरण को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि जब तक गाँव आत्मनिर्भर नहीं होंगे और स्थानीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग नहीं किया जाएगा, तब तक भारत की आर्थिक प्रगति अधूरी रहेगी।

हालाँकि, वे गांधीवादी विचारधारा के इस पहलू से असहमत थे कि केवल नैतिकता के आधार पर राजनीतिक परिवर्तन लाया जा सकता है। लोहिया मानते थे कि नैतिक मूल्यों के साथ–साथ ठोस नीतियों और योजनाओं की भी आवश्यकता होती है। उनका विचार था कि कभी–कभी सामाजिक न्याय और परिवर्तन के लिए आक्रामक संघर्ष भी अपरिहार्य हो सकता है। इस प्रकार, लोहिया का समाजवाद गांधीवाद और क्रांतिकारी समाजवाद का एक अनूठा समन्वय था, जो सामाजिक और राजनीतिक सुधारों

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 2, November 2025 Impact Factor: 7.67

को प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास करता था।

4. कांग्रेस और भारतीय राजनीति पर विचार–

डॉ. राम मनोहर लोहिया स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की नीतियों के मुखर आलोचक बने। वे मानते थे कि कांग्रेस, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी, अब सत्ता के केंद्रीकरण और वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देने लगी थी। उनका विचार था कि लोकतंत्र में एक–पार्टी वर्चस्व खतरनाक होता है, क्योंकि यह सत्ता को निरंकुश बना सकता है और विरोधी विचारों को दबा सकता है। इसी कारण उन्होंने नेहरू सरकार की नीतियों का कड़ा विरोध किया और यह तर्क दिया कि यदि लोकतंत्र को जीवंत और प्रभावी बनाए रखना है, तो समाजवादी और अन्य विचारधाराओं को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर दिया जाना चाहिए।

लोहिया ने कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए ष्कांग्रेस हटाओ, देश बचाओष् का नारा दिया। उनका मानना था कि कांग्रेस के दीर्घकालिक शासन ने सत्ता के संतुलन को बिगाड़ दिया है और इसकी नीतियाँ केवल अभिजात्य वर्ग के हितों की रक्षा कर रही हैं, जबकि समाज के गरीब और वंचित तबके हाशिए पर धकेले जा रहे हैं। उन्होंने विपक्षी दलों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया और समाजवादी विचारधारा के आधार पर एक सशक्त राजनीतिक विकल्प खड़ा करने का प्रयास किया।

लोहिया के नेतृत्व में कई क्षेत्रीय और समाजवादी दलों को प्रेरणा मिली, जिससे भारतीय राजनीति में बहुदलीय लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई। उनकी सोच ने विपक्ष को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया, जिससे आगे चलकर गैर–कांग्रेसी सरकारों का उदय हुआ। 1967 के चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन बनाने की उनकी रणनीति सफल रही, और कई राज्यों में गैर–कांग्रेसी सरकारें बनीं।

लोहिया का यह दृष्टिकोण भारत में एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे के निर्माण में सहायक बना। उनकी नीतियों ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी राजनीतिक दल को अनियंत्रित रूप से सत्ता पर काबिज नहीं रहना चाहिए और एक प्रभावी विपक्ष लोकतंत्र के लिए अनिवार्य होता है। उनकी यह सोच आज भी भारतीय राजनीति में प्रासंगिक बनी हुई है।

5. विदेश नीति और राष्ट्रवाद –

डॉ. राम मनोहर लोहिया की विदेश नीति स्वतंत्र सोच पर आधारित थी और वे किसी भी प्रकार की बाहरी दबाव नीति के खिलाफ थे। उन्होंने भारत की गुटनिरपेक्षता का समर्थन किया, लेकिन इसे केवल एक कूटनीतिक सिद्धांत के रूप में अपनाने के बजाय, व्यावहारिक रूप से देशहित में लागू करने की वकालत की। उनका मानना था कि भारत को न तो पश्चिमी पूंजीवादी देशों के प्रभाव में आना चाहिए और न ही सोवियत संघ के समाजवादी गुट का अंधानुकरण करना चाहिए। इसके बजाय, भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनानी चाहिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्वायत्तता को प्राथमिकता दे।

लोहिया केवल कूटनीतिक तटस्थता के पक्षधर नहीं थे, बल्कि वे यह भी मानते थे कि भारत को अपनी रक्षा नीति को मजबूत करना चाहिए। वे चीन और पाकिस्तान की आक्रामक नीतियों को लेकर स्पष्ट रूप से सचेत थे और इन देशों की विस्तारवादी मानसिकता का विरोध करते थे। 1962 के भारत–चीन युद्ध और 1965 के भारत–पाक युद्ध के दौरान उन्होंने सरकार की कमजोरी और रक्षा नीति की खामियों की आलोचना की। वे इस बात पर जोर देते थे कि भारत को अपनी सैन्य शक्ति और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए, ताकि बाहरी आक्रमणों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 2, November 2025
Impact Factor: 7.67

सके।

इसके साथ ही, लोहिया भारत की आर्थिक और औद्योगिक स्वतंत्रता को भी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू मानते थे। वे चाहते थे कि भारत विदेशी पूंजी और तकनीक पर अत्यधिक निर्भर न रहे, बल्कि अपने संसाधनों और क्षमताओं का उपयोग करके आत्मनिर्भर बने। उनका मानना था कि यदि भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनना है, तो उसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि और रक्षा उत्पादन के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना होगा।

लोहिया की विदेश नीति में एक स्पष्ट राष्ट्रवादी दृष्टिकोण था, जो न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा पर बल देती थी, बल्कि आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक स्वतंत्रता को भी समान रूप से महत्वपूर्ण मानती थी। उनके विचारों ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और आत्मनिर्भर रक्षा रणनीति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

6. महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता –

डॉ. राम मनोहर लोहिया नारी सशक्तिकरण के एक सशक्त पैरोकार थे। उनका मानना था कि किसी भी समाज में वास्तविक समानता तब तक स्थापित नहीं हो सकती, जब तक महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार और अवसर नहीं मिलते। वे केवल औपचारिक समानता की बात नहीं करते थे, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को अनिवार्य मानते थे।

लोहिया का विचार था कि समाजवाद की सफलता का आकलन इस बात से किया जाना चाहिए कि वह महिलाओं को कितना सशक्त बना पाता है। उन्होंने स्त्री–पुरुष समानता को अपनी ष्सप्त क्रांतिष् के प्रमुख स्तंभों में शामिल किया और इसे सामाजिक परिवर्तन के लिए अनिवार्य बताया। वे मानते थे कि जब तक महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में समान अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक समाज में संतुलित विकास संभव नहीं होगा।

उन्होंने राजनीतिक भागीदारी के संदर्भ में महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की मांग की और कहा कि बिना महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लोकतंत्र अधूरा रहेगा। उनका मानना था कि संसद, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि वे नीतिगत निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

आर्थिक क्षेत्र में भी लोहिया महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के पक्षधर थे। वे मानते थे कि महिलाओं को केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वरोजगार, उद्योग–धंधों और सेवा क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को समान वेतन और कार्यस्थल पर सम्मानजनक माहौल मिलना चाहिए, ताकि वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकें।

लोहिया ने यह भी स्पष्ट किया कि नारी स्वतंत्रता का अर्थ केवल कानूनी अधिकारों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाकर महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर देने चाहिए। उनके विचार आज भी महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता की दिशा में प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं।

7. औद्योगीकरण बनाम विकेंद्रीकरण –

डॉ. राम मनोहर लोहिया का आर्थिक दृष्टिकोण औद्योगीकरण और विकेंद्रीकरण के संतुलित विकास पर आधारित था। वे मानते थे कि केवल भारी उद्योगों पर अत्यधिक निर्भरता देश की आर्थिक संरचना को असंतुलित कर सकती है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। उनका विचार था कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 2, November 2025 Impact Factor: 7.67

आवश्यक है, ताकि देश के हर कोने में आर्थिक गतिविधियाँ विकसित हो सकें और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलें।

लोहिया का मानना था कि भारी उद्योगों के विस्तार से शहरीकरण और पूंजी का केंद्रीकरण बढ़ता है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानता गहराती है। इसलिए उन्होंने एक ऐसी अर्थव्यवस्था की वकालत की, जो ग्रामीण भारत को सशक्त बनाए और वहां की श्रम शक्ति को प्रभावी रूप से उपयोग में लाए। वे चाहते थे कि कपड़ा, हथकरघा, कुम्हार गिरी, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, कृषि उपकरण निर्माण और अन्य पारंपरिक उद्योगों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए, ताकि वे टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी बन सकें।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था से स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गरीब तबकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। लोहिया यह मानते थे कि यदि सरकार छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों को समर्थन दे, तो देश में एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था विकसित की जा सकती है।

इसके अलावा, लोहिया उत्पादन और उपभोग के बीच संतुलन बनाए रखने के पक्षधर थे। वे मानते थे कि देश की अर्थव्यवस्था को ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहिए, जहाँ स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर उत्पादन किया जाए, ताकि लोगों की जरूरतें पूरी होने के साथ–साथ आत्मनिर्भरता भी बढ़े। उनका यह दृष्टिकोण आज भी सतत विकास की नीति के रूप में प्रासंगिक बना हुआ है, जिसमें स्थानीय और विकेंद्रीकृत उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है।

निधन और विरासत –

12 अक्टूबर 1967 को 57 वर्ष की उम्र में डॉ. लोहिया का निधन हो गया। उनकी समाजवादी विचारधारा आज भी भारतीय राजनीति और सामाजिक आंदोलनों को प्रेरित करती है। वे केवल एक राजनेता ही नहीं, बल्कि क्रांतिकारी विचारक, लेखक और समाज सुधारक भी थे। उनकी विरासत को कई समाजवादी दल आज भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके विचारों पर आधारित राजनीति ने भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं और वे आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं।

निष्कर्ष :–

डॉ. राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक विचार आज भी भारतीय राजनीति के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। उन्होंने समाजवाद को भारतीय संदर्भ में ढालकर सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता का समन्वय किया। जाति–प्रथा के विरोध और 'पिछड़ों को 60प्रतिशत' के नारे ने सामाजिक न्याय की दिशा में नई सोच दी। महिला सशक्तिकरण पर उनके विचार आज भी नीति–निर्माण को प्रभावित करते हैं। वे सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ थे और विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली के समर्थक थे। उनकी आर्थिक नीतियाँ लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने पर केंद्रित थीं, जो आज भी आत्मनिर्भर भारत के विचार से मेल खाती हैं। उन्होंने विपक्ष की ताकत को लोकतंत्र के लिए आवश्यक माना और 'कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ' का नारा देकर बहुदलीय राजनीति को मजबूती दी। उनकी विदेश नीति आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित थी। उन्होंने केवल आलोचना नहीं की, बल्कि वैकल्पिक नीतियों का प्रस्ताव भी रखा। भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलनों में उनका योगदान अमिट है, जो आने वाले समय में भी प्रेरणा देता रहेगा।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 2, November 2025
Impact Factor: 7.67

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

[1]. लोहिया, राम मनोहर : व्हील ऑफ हिस्ट्री।

[2]. लोहिया, राम मनोहर : मार्क्स, गाँधी एण्ड सोशलिज्म।

[3]. वर्मा, डॉ.वी.पी. : आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन।

[4]. नागर, डॉ. पुरुषोत्तम : आधुनिक भारतीय एवं राजनीकि चिंतन।

[5]. संग्रहित प्रति मूल से 14 नवंबर 2006 को पुरोलेखित :7 अभिगमन तिथि 23 मार्च 2009

[6]. रमैया, पट्टाभिसीता : दि हिस्ट्री ऑफ दि कांग्रेस।

[7]. सिंह, प्रताप : गाँधी जी का दर्शन।

[8]. भट्टाचार्य, डॉ. प्रभात कुमार : गाँधी दर्शन।

[9]. नेहरू, पं. जवाहर लाल : आटावायग्राफी ।

[10]. फाड़िया, वी.एस. : आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन।

[11]. इंडिया टुडे नई दिल्ली

[12]. आजकल, नई दिल्ली

[13]. माया प्रयागराज

[14]. द हिन्दू समाचार पत्र वाराणसी

[15]. जनसत्ता, दिल्ली